(a) whether employment has not grown in proportion to the massive investment that has already taken place in the public and the private sectors ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to synchronise the employment growth with the investments ?

THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c). Additional employment opportunities on a substantial scale have been generated as a result of the investments made on the programmes executed as part of the Development Plans of the Country. The Planning Commission have estimated that additional jobs of the order of 31 5 million were created in the first three Five-Year Plans.

In the context of a country's development, several considerations besides employment generation, such as development of heavy industries, defence needs etc. have to be kept in view However, the need for maintaining a close relationship between the rate of economic growth and the rate of employment growth has recently been increasingly recognised by the Government and the Fourth Plan, a major objective of which is to create larger employment opportunities in the rural and urban areas, lays considerable emphasis on the promotion of labour-intensive schemes, such as road construction, soil conservation, mining, irrigation, rural electrification, village and small-scale industries etc. Apart from programmes included in the Fourth Plan a number of special employment-oriented schemes, designed for the benefit of the weaker sections of the society, have been undertaken during the year 1970-71. Important among these are : (1) scheme for development of small but potentially viable farmers ; (2) scheme for marginal farmers and agricultural labourers ; (3) development of dry farming ; (4) rural works programmes ; (5) scheme for area developments ; (6) scheme for dairy development. Special emphasis is also being laid on the promotion of medium and small-scale industries which have a considerable employment potential. More recently the Government have also sanctioned a crash programme for rural employment for which a sum of Rs. 50 crores has been provided for the year 1971-72. The scheme envisages the employment of a minimum of 1,000 persons in each district of the country on works of an infra-structure nature. The Government also propose reviewing the progress of the Fourth Plan with a view to reinforcing the development programmes for the generation of more employment.

मध्य प्रदेश के मन्दसौर तथा रतलाम जिलों में टेलीफोन केन्द्रों की सुविधाएं

149. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्दसौर तथा रतलाम जिलों (मध्य प्रदेश) मे उन स्थानो के नाम क्या है जहा पर टेलीफोन केन्द्रो की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या रतलाम जिले के गावारा टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढाने का कार्य प्रगति पर है ; और

(ग) यदि हा, तो कब से ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) मन्दसौर जिले मे निम्नलिखित एक्सचेंज काम कर रहे है :—

(i) मन्दसौर (2) नीमज (3) शामगढ (4) मानपुरा (5) गरोठ (6) जावद (7) मल्हारगढ (8) मनासा (9) पीपलिला (10) रायपुरा (11) सीतामऊ और (12) सुवासरा मंडी ।

(ii) रतलाम जिले मे काम कर रहे एक्सचेंजो के नाम इस प्रकार है :—

(1) रतलाम (2) आलोट (3) गावारा और (4) सेलाना ।

(ख) तथा (ग). रतलाम जिले में गावारा

नाम का कोई एक्सचेंज नहीं है। फिर भी जावरा में एक एक्सचेंज है। जावरा में 100 लाइनों का एक लघु स्वचालित एक्सचेंज काम कर रहा है। इसे बदल कर 200 लाइनों का एम० ए० एक्स० II किस्म का एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कुछ उपस्कर प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होनी है। आशा है कि 1971 के मध्य तक उपलब्ध हो जाएगी।

Income out of Advertisements over A. I R.

150 SHRI M RAM GOPAL REDDY Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the income, year-wise, derived by Government out of the commercial advertisements broadcast over the All India Radio ever since introduction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) The year wise gross income from the Commercial Service since its introduction in November 1970, is as follow

1967	Rs	7,55,400
1968	Rs	63,56,237
1969	Rs	2,01,73,834
1970	Rs	2 65,32,192
1971	Rs	57,85,367

(January and February)

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में डाक व तार घरों का खोला जाना

151. **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन के मुरैना जिले में इस वर्ष नये डाक व तार घर खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कितने डाक घर खोले जायेंगे।

(ख) नये डाक व तार घर कब तक खोल दिये जायेंगे। और ये डाक व तार घर किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(ग) नगरीय तथा देहाती क्षेत्रों में अलग अलग कितने डाक व तार घर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) 1971-72 के वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन के मुरैना जिले में 16 डाक घर और 2 तार घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) 1971-72 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक निम्नलिखित स्थानों पर नए डाक घर और तार घर खोल जाने की सम्भावना है।

डाक घर	तार घर
किशनपुर	बोरपुर
सिरमौर	शिवपुर बड़ौदा
कापुर	
पचमपुरा	
नयापारा	
परीचा	
डूडपारा	
गड्डाई	
बोरडा	
कठऊ	
कलहौ	
बड्डीपारा	
सुहनी	
दिनतोखरकलां	
देवपुर	
मावी	

(ग) डाक घर

शहरी क्षेत्रों में 2 उप-डाक घ
क्षेत्रों में 14 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक-घर खोलने का प्रस्ताव है।